कानपुर, सोमवार, 2 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 33, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड केंद्रीय बजट में यूपी को तोहफों के ढेर...>Pg12

1990 से फरार, 2017 में इनामी, 2026 में गिरफ्तार...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

जनप्रतिनिधियों को बड़ी राहत

आचार संहिता उल्लंघन के केस रफा-दफा

इन जनप्रतिनिधियों को मिली राहत

- **महोबा** - उमा भारती
- **मुजफ्फरनगर** - डॉ. संजीव बालियान, राजपाल बालियान
- **अलीगढ़** - ठाकुर जयवीर सिंह
- **शामली** - सुरेश राणा, अशरफ अली खान
- **आजमगढ़** - नीलम सोनकर
- **उन्नाव** - अनिल सिंह
- **कानपुर** - अभिजीत सिंह सांगा
- **जौनपुर** - सीमा द्विवेदी
- **बुलंदशहर** - विजेंद्र सिंह, मीनाक्षी सिंह
- **कुशीनगर** - विवेकानंद पांडे
- **महाराजगंज** - जय मंगल कनौजिया
- **हाथरस** - प्रदीप चौधरी

❍ फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति के बाद लागू होगा

❍ सभी मामले निचली अदालतों से औपचारिक रूप से वापस लिए जाएंगे

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज 28 छोटे आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। ये मुकदमे कोविड-19 लॉकडाउन उल्लंघन, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी आदेशों की अवज्ञा जैसे मामलों से जुड़े थे। हाईकोर्ट के इस फैसले को जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

हाईकोर्ट ने माना कि ये मामले गंभीर आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं। सार्वजनिक व्यवस्था या समाज पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। मुकदमे वापस लेने से न्याय प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। इसके पूर्व प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि अधिकांश मुकदमे महामारी काल में लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान दर्ज हुए। चुनावी गतिविधियों के समय तकनीकी उल्लंघन के कारण बने। इनमें हिंसा, भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक मंशा शामिल नहीं है। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाना न्यायिक संसाधनों का दुरुपयोग होगा।

यूपी में जनप्रतिनिधियों के 28 केस वापस लेने को हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

इन मामलों को माना गया 'छोटा अपराध'

- कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन
- चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन
- प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना
- राजनीतिक हलकों में सियासी हलचल
- हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
- सत्तापक्ष इसे व्यवहारिक और न्यायसंगत फैसला बता रहा है
- विपक्ष ने कानून के समान अनुप्रयोग पर सवाल खड़े किए हैं

69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में उबाल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का विरोध सोमवार को राजधानी लखनऊ में उग्र हो गया। डिप्टी सीएम आवास के घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सपा कार्यालय के बाहर ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते-देखते धक्का-मुक्की में बदल गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर वाहनों से निर्धारित प्रदर्शन स्थल इको गार्डन भेज दिया। बताया गया कि करीब 50 अभ्यर्थी सुबह 11 बजे सपा कार्यालय के बाहर एकत्र हुए थे। अभ्यर्थी अपने कंधों पर नारे लिखे बैनर ओढ़े हुए थे और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं व आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध जता रहे थे।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रोक-टोक के दौरान पुलिस ने उनके बैनर फाड़ दिए, जिससे आक्रोश और भड़क गया। करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा और भर्ती प्रक्रिया में न्याय की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति संवेदनशील क्षेत्र की ओर जुलूस ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे रोकना जरूरी था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों को हटाकर इको गार्डन भेजा गया है। पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई।

- **डिप्टी सीएम आवास घेरने निकले अभ्यर्थी रोके गए**
- **पुलिस-अभ्यर्थियों में तीखी नोकझोंक, धक्का-मुक्की से बिगड़ा माहौल**
- **ना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप, पुलिस ने कार्रवाई को बताया जरूरी**

राहुल गांधी के डोकलाम बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह ने दी खुली चुनौती

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डोकलाम क्षेत्र में चीनी सेना के टैंक मौजूद होने के दावे पर जोरदार हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के हवाले से यह दावा किया और एक अप्रकाशित पुस्तक का संदर्भ दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि अप्रकाशित पुस्तक पर आधारित दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता और राहुल गांधी से स्पष्ट जवाब मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में केवल प्रकाशित और प्रमाणित संदर्भों पर ही चर्चा होनी चाहिए।

विवाद बढ़ने पर राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरणों का हवाला देने की बात कही। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सदन के बाहर के संदर्भों के इस्तेमाल का पक्ष रखा। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चीन मुद्दा संवेदनशील है और विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। शोर-शराबे के बीच स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सदस्यों को केवल निर्धारित विषय पर ही चर्चा करने की चेतावनी दी।

डोकलाम में चीनी टैंकों के दावे और अप्रकाशित पुस्तक का हवाला, स्पीकर को बीच-बचाव करना पड़ा

- ❍ राहुल गांधी ने डोकलाम क्षेत्र में चीनी टैंकों की मौजूदगी का दावा किया।
- ❍ दावा पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और अप्रकाशित पुस्तक पर आधारित बताया।
- ❍ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुस्तक अप्रकाशित होने का हवाला देते हुए खुली चुनौती दी।
- ❍ गृह मंत्री अमित शाह ने केवल प्रकाशित और प्रमाणित स्रोतों पर चर्चा की वकालत की।
- ❍ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सदन के बाहर के संदर्भों के इस्तेमाल का पक्ष रखा।
- ❍ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्ष को बोलने का अवसर देने की बात कही।
- ❍ स्पीकर ओम बिरला को लगातार हंगामे के बीच हस्तक्षेप करना पड़ा।

बजट को लेकर किसी ने कहा कुछ खास नहीं, कोई बोला बहुत अच्छा

इस साल के आम बजट में कोई खास प्रगति नहीं, सिर्फ पुराने कॉलम दोहराए गए

स्वराज इंडिया , कानपुर। आम बजट को लेकर देशभर में मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। करदाताओं को राहत देते हुए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई गई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मध्यम वर्ग ने समय सीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया, जबकि उद्योग जगत ने इसे अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला कदम बताया। वहीं विपक्ष का कहना है कि टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से आम आदमी को वास्तविक राहत नहीं मिल सकी। कुल मिलाकर बजट पर संतुलित लेकिन सतर्क प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

उच्च शिक्षा और नवाचार को नई उड़ान देगा यह बजट

केंद्रीय बजट में उच्च शिक्षा, विशेषकर IITs, NITs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बढ़ा हुआ आवंटन शोध एवं नवाचार के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना, शोध परियोजनाओं और अकादमिक गुणवत्ता को नई गति मिलेगी। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र से जोड़ने की पहल, शोध छात्रों सहित युवाओं को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगी। यह अकादमिक ज्ञान और उद्योग के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। AI और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान तथा शिक्षा ऋण को सरल बनाने की व्यवस्था, उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और भविष्य-उन्मुख बनाती है। यह बजट भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आशाजनक है।

दिनेश यादव
शोध छात्र
वी.एस.एस.डी कॉलेज, कानपुर

बजट कागज़ पर विकास, आम जीवन में अधूरी अपेक्षाएँ

बजट की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब इसके प्रावधान नीति, बजट क्रियान्वयन और जनजीवन के संतुलित असर के रूप में जमीन पर दिखाई दें। यह बात सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहाकि केन्द्रीय बजट 2026 देश की आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास की दिशा को रेखांकित करता है। इसमें उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को गति देने के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।फिर भी, आम जीवन पर बजट का ठोस असर अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। युवाओं के रोजगार सृजन, गरीब एवं मध्यम वर्ग की प्रत्यक्ष राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, कृषि एवं कृषक आय-सुरक्षा, न्यायिक ढांचा,विशेषकर जिला न्यायालय ,इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम अभी नहीं दिख रहे। शेयर बाजार और वित्तीय संकेत यह दर्शाते हैं कि निवेशकों और आम जनता का विश्वास अभी पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हुआ है।

जितेन्द्र चौहान
सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता

बजट में कर्मचारियो को निराशा

कर्मचारियो शिक्षकों को बजट में मानक आयकर कटौती 2.50 लाख न करने,कर्मचारी व पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त धनराशि को आयकर गणना से छूट न देने । 18 माह करोना काल के काटे गए भत्ते का भुगतान कराया न जारी करने,सरकारी कर्मचारियों को आवास बनवाने हेतु 3 प्रतिशत ब्याज दर पर होम लोन की व्यवस्था न करने । सरकारी कर्मचारियों को वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य जरूरी वस्तुओं के खरीदने के लिए जीएसटी मुक्त कैंटीन न खुलवाने व आयकर स्लैब में छूट न देने से कर्मचारियों को घोर निराशा हुई है।यह बजट कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स विरोधी है।

राजा भरत अवस्थी प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश

टैक्स प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने वाला बजट

बजट 2026 कर की दरों में बदलाव से कहीं अधिक टैक्स प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने वाला बजट है। नया 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' पेश करना और 'असेसमेंट ईयर' की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर 'टैक्स ईयर' लागू करना एक युगांतकारी कदम है, जिससे टैक्स कंप्लायंस पूरी तरह पेपरलेस और सुगम हो जाएगा। MSMEs को सशक्त बनाने के लिए 10,000 करोड़ का 'SME Growth Fund' और 'कॉर्पोरेट मित्र' जैसी योजनाएं उन्हें ढांचागत मजबूती प्रदान करेंगी, जबकि TDS/TCS दरों में की गई कटौती से आम व्यापारियों के हाथ में वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता बढ़ेगी। हालांकि, इस नए एक्ट के ट्रांजिशन फेज में टैक्स प्रैक्टिशनर की भूमिका और जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन भविष्य में यह बदलाव एक पारदर्शी और 'ट्रस्ट-बेस्ड' टैक्स व्यवस्था की नींव रखने में मील का पत्थर साबित होगा।

सिमरन जीत सिंह
टैक्स प्रैक्टिशनर

कर्मचारियों के हित को हाशिए पर धकेला

"आज प्रस्तुत हुआ केंद्रीय बजट एक बार फिर देश के विकास की धुरी माने जाने वाले 'सरकारी कर्मचारियों' और 'मध्यम वर्ग' के लिए पूरी तरह से निराशाजनक और उत्साहहीन रहा है। सरकार ने बड़े-बड़े दावों के बीच उस वर्ग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है जो पूरी ईमानदारी से टैक्स भरता है और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारता है।

यह बजट 'सबका साथ' की बात तो करता है, लेकिन 'कर्मचारियों के हित' को हाशिए पर धकेल देता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करे और कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।

शशिकांत अवस्थी,
मण्डल अध्यक्ष,
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद,
कानपुर।

1990 से फरार, 2017 में इनामी, 2026 में गिरफ्तार

50 हजार का इनामी हत्यारोपी 'शौकत' गिरफ्तार, 35 साल तक नाम-भेष बदल कर रहा

कानपुर। नाम बदला, पहचान बदली, ठिकाने बदलेज तीन दशक से ज़्यादा वक्त तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा शातिर हत्यारोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। कानपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन अंतर्गत थाना कर्नलगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने 35 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर अपराध की दुनिया को साफ संदेश दे दिया कानून से भागना चाहे जितना लंबा हो, अंत तय है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शौकत पुत्र वसीर, निवासी साहिबाबाद थाना चमनगंज, पर वर्ष 1984 में थाना कर्नलगंज क्षेत्र में रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप है। घटना के बाद आरोपी जेल गया, लेकिन जमानत पर बाहर आते ही 1990 से फरार हो गया। इसके बाद शौकत ने योजनाबद्ध तरीके से अपना नाम, पहचान और ठिकाना बदल लिया। वह दूसरे जिले में जाकर नई पहचान के साथ रहने लगा, जिससे पुलिस को लंबे समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। लगातार फरारी और साक्ष्यों के अभाव में आरोपी वर्षों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। आखिरकार वर्ष 2017 में पुलिस ने उसे 50 हजार का इनामी घोषित किया, लेकिन इसके बावजूद वह कानून को खुली चुनौती देता रहा और लगातार पहचान छिपाकर रह रहा था।

तकनीक, सर्विलांस और खुफिया सूचना से टूटी 35 साल की चुप्पी

सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम प्रभारी लोकेंद्र कुमार और थाना कर्नलगंज प्रभारी विनीत चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत आरोपी की वर्षों पुरानी परतें खोली गईं। तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की वर्तमान लोकेशन ट्रेस की और उसे जनपद गोंडा से दबोच लिया। इस बड़ी कार्रवाई में सर्विलांस टीम के लवकुश मिश्रा, धर्मेंद्र तिवारी, नवीन, शरद, राहुल अग्रहरि तथा थाना पुलिस से उप निरीक्षक रिंकू निमेष और दिनेश मौर्या की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम के अथक प्रयासों ने 35 साल पुराने हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी। इस गिरफ्तारी को सेंट्रल जोन पुलिस की बड़ी और सराहनीय उपलब्धि माना जा रहा है। यह न सिर्फ वर्षों पुराने हत्या मामले को न्याय की दिशा में ले जाने वाली कार्रवाई है, बल्कि अपराधियों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है कि नाम बदलने, भेष बदलने या जिला बदलने से कानून से नहीं बचा जा सकता।

➪ **कर्नलगंज पुलिस और सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी**

ढाई माह से लापता किशोरी बरामद, आरोपी युवक बैंगलुरु से गिरफ्तार

प्रमुख संवाददाता

कानपुर। सचेंडी थाना क्षेत्र के एक गांव से 24 नवंबर को लापता हुई दो नाबालिग बहनों में से एक किशोरी को ढाई माह बाद पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरण के मुख्य आरोपी महेश को बैंगलुरु से गिरफ्तार किया है।

➪ **24 नवंबर को लापता हुई दो नाबालिग बहनें, एक लौट आई थी**

मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर दो युवकों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। 7 दिसंबर को दोनों में से एक किशोरी अपने घर लौट आई थी, लेकिन दूसरी का कोई पता नहीं चल सका। परिवार और गांव में किशोरी की गुमशुदगी को लेकर चिंता का माहौल बना रहा।

पुलिस ने लगातार सर्विलांस और छानबीन कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की। इसकी सफलता तब मिली जब ट्रैकिंग के जरिए महेश को बैंगलुरु से दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को कानपुर लाकर पुलिस ने किशोरी की सुरक्षा सुनिश्चित की।

सचेंडी थाना पुलिस ने बताया कि किशोरी को सुरक्षित घर भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने को दें।

- सचेंडी थाना क्षेत्र के गांव से 24 नवंबर को लापता हुई दो नाबालिग बहनों में से एक किशोरी बरामद।
- आरोपी युवक महेश को पुलिस ने बैंगलुरु से गिरफ्तार किया।
- पीड़िता की मां की तहरीर पर दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था।
- 7 दिसंबर को दूसरी किशोरी अपने घर लौट आई थी, तीसरे का कोई सुराग नहीं मिला था।
- पुलिस की सर्विलांस और छानबीन के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली।
- गिरफ्तार आरोपी को कानपुर लाकर किशोरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

कानपुर में कारोबारी के जीएसटी खाते में सेंध, 70 करोड़ की फर्जी रिटर्न फाइल

प्रमुख संवाददाता

कानपुर। रावतपुर थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के जीएसटी खाते में अनधिकृत प्रवेश कर करोड़ों रुपये की फर्जी रिटर्न दाखिल करने का मामला सामने आया है। राधाबिहार निवासी कारोबारी उत्कर्ष सविता ने बताया कि उनके जीएसटी पंजीकरण से जुड़े मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को बदले जाने के बाद किसी अज्ञात साइबर ठग ने उनके खाते तक अनधिकृत पहुंच बनाई।

अक्टूबर 2025 के अंत में कारोबारी को अपने जीएसटी खाते में लॉगिन करने में समस्या हुई। शिकायत दर्ज कराने के बाद नवंबर 2025 में पता चला कि उनके खाते से किसी अन्य फर्म के नाम पर 70 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी रिटर्न फाइल कर दी गई थी। जांच में करीब 12.66 करोड़ रुपये की टैक्स धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। रावतपुर पुलिस ने साइबर सेल की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपी और उनके नेटवर्क की पहचान के प्रयास जारी हैं और जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

➪ **मोबाइल और ई-मेल बदलकर साइबर ठग ने बनाई अनधिकृत पहुंच, 12.66 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा**

दुष्कर्म पीड़िता ने वकील पर लिखाया ठगी का मुकदमा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के जूही क्षेत्र की एक दुष्कर्म पीड़िता ने अधिवक्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि वकील ने मुआवजा दिलाने का झांसा देकर उससे करीब ढाई लाख रुपये हड़प लिए और बाद में आरोपित पक्ष से साठगांठ कर ली। विरोध करने पर अधिवक्ता ने जान से मारने और फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और धमकी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के अनुसार, उसने पिछले वर्ष जूही थाने में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विधिक सहायता के लिए उसने एक अधिवक्ता से संपर्क किया। आरोप है कि अधिवक्ता ने सरकारी मुआवजा दिलाने का भरोसा देकर कैनरा बैंक की लायर्स एसोसिएशन शाखा में उसका खाता खुलवाया और सादे कागजों व चेकबुक पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लिए।

अलग-अलग तारीखों में ऑनलाइन और नकद मिलाकर लगभग 2.5 लाख रुपये भी ले लिए।पीड़िता का कहना है कि जब उसने चेकबुक वापस मांगी तो हस्ताक्षर किए हुए चेक गायब मिले। रकम और दस्तावेज लौटाने को कहने पर अधिवक्ता ने उसे धमकाया। कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है

➪ **मुआवजा दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपये लेने और साठगांठ का आरोप**

➪ **विरोध करने पर जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी**

मुंबई की युवती को प्रेमी ने पत्नी संग मार डाला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुंबई। गोरखपुर के पीपीगंज में मिले युवती के शव की पहचान हो गई है। युवती मुंबई की थी। उसकी हत्या प्रेमी ने पत्नी संग मिलकर की थी। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस से पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। शादी का दबाव बनाने पर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सहजनवां के दंपती समेत तीन हिरासत में लिए हैं। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में हत्या कर फेंका गया शव मुंबई की युवती प्रिया का था। पुलिस की जांच के मुताबिक, युवती का प्रेम प्रसंग सहजनवां इलाके के एक शादीशुदा युवक विजय के साथ चल रहा था। युवती शादी का दबाव बना रही थी। युवक ने पीछा छुड़ाने के लिए पत्नी संध्या के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। शव की पहचान छिपाने के लिए चेहरा ईंट से कूच दिया। इसके बाद उसे निर्वस्त्र करके झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस दंपती विजय-संध्या समेत तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सोमवार को घटना का पर्दाफाश करेगी।

शरीर पर इसलिए न छोड़ा एक भी कपड़ा; प्रिया के कत्ल की कहानी

10 साल पहले हुई थी विजय की शादी

विजय की शादी 10 साल पहले पीपीगंज वार्ड नंबर पांच सपहिया निवासी संध्या से हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। आठ साल की बेटी और दो साल का बेटा है। विजय की सास यशोदा को जब वारदात की जानकारी हुई तो वह सदमे में आ गईं। पहले तो वह कुछ भी बताने से इन्कार करती रहीं, लेकिन बाद में फफक कर रो पड़ीं। उनका कहना है कि बेटी और दामाद की नादानी के चलते उनके दोनों मासूम बच्चों का अब भविष्य भी खतरे में पड़ गया है।दंपती समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव की शिनाख्त के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी

पुलिस जांच के अनुसार, सहजनवां थाना क्षेत्र के मारड़ पाली गांव का निवासी विजय मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। वहां उसकी मुलाकात प्रिया नामक युवती से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। दोनों लिव इन में भी रहने लगे। प्रिया जब शादी करने और घर ले चलने का दबाव बनाने लगी तब विजय उसे छोड़कर मुंबई से भाग आया था।

यहां आने पर कुछ दिन तक बातचीत करता रहा। प्रेमी को पीछा छुड़ाता देख प्रिया उसकी तलाश करते हुए पीपीगंज पहुंच गई।यहां आने के बाद उसे पता चला कि विजय शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। हालांकि प्रिया उसकी दूसरी पत्नी बनने को तैयार थी, लेकिन उसकी पहली पत्नी संध्या को यह मंजूर नहीं था। आरोप है कि घर में कलह बढ़ने पर विजय और उसकी पत्नी संध्या ने मिलकर युवती की हत्या की साजिश रची।

इसके तहत विजय प्रिया को ससुराल लेकर गया और वहां उसे खूब शराब पिलाई गई। फिर अपने साले के साथ स्कूटी पर उसे ले जाकर गला दबाया और चेहरे को ईंट से कूंच दिया।

इसके बाद शव को निर्वस्त्र कर पीपीगंज थाना क्षेत्र के गोबरहिया नाले के पुल के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी जानते थे कि कपड़े और अन्य सामान से पुलिस पहचान कर सकती है। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले।

सीसीटीवी फुटेज से पर्दाफाश

शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। पीपीगंज कस्बे में इलाहाबाद बैंक के सामने लगे कैमरे में नीली स्कूटी पर दो संदिग्ध युवक कैद हो गए। यही फुटेज पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुई। दरअसल, पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की तो वारदात वाली रात करीब 11:20 बजे एक नीली स्कूटी पर तीन लोग जाते दिखे, जबकि वापसी में करीब 12 बजे केवल दो लोग ही लौटे। इन्हें संदिग्ध मानकर पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की।

इसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों से संपर्क कर वारदात की जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि मुंबई से प्रिया के परिवार के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। इस बीच आरोपियों से पूछताछ जारी है।

रेलवे कर्मी ससुर की स्कूटी से प्रिया के शव को लगाया था ठिकाने

मुंबई की युवती की हत्या में पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी विजय ने प्रिया को गांव में न रखकर पीपीगंज में किराए के एक मकान में ठहराया था। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए विजय ने रेलवे में तैनात अपने ससुर की स्कूटी का इस्तेमाल किया। यहीं नहीं लौटते समय प्रिया के कपड़े अलग कर नदी किनारे फेंक दिए ताकि पुलिस और परिजन उसकी पहचान न कर सकें।पुलिस ने इस मामले में विजय की पत्नी संध्या और उसकी साली को भी हिरासत में लिया है। उसकी साली पीपीगंज में ब्यूटी पार्लर संचालित करती है। पूछताछ से पता चला है कि हत्या की साजिश में केवल विजय ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। वहीं किराए के कमरे में युवती को रखने के दौरान आरोपी ने उसका आधार कार्ड बनवाने और शादी का झांसा दिया था।

कक्षा 12 बोर्ड रसायन विज्ञान में सफलता का मंत्र: सिस्टेमेटिक तैयारी से बढ़ेंगे अंक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में रसायन विज्ञान में अच्छे अंक लाने के लिए सिस्टेमेटिक और नियमित तैयारी बेहद जरूरी है। विषय विशेषज्ञों के अनुसार विद्यार्थियों को एनसीईआरटी को आधार बनाकर अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिलेबस को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के हिस्सों में बांटकर पढ़ाई करने से समझ आसान होती है।

हाई वेटेज अध्यायों जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पहले फोकस करने की सलाह दी गई है। पढ़ाई को व्यवस्थित रखने के लिए चेकलिस्ट बनाकर हर टॉपिक पूरा होने पर टिक मार्क करना उपयोगी माना जा रहा है।

स्टडी प्लान के तहत रोजाना 2-3 घंटे रसायन विज्ञान को देने चाहिए, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और रिवीजन शामिल हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला चार्ट, इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोटस और ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन्स लिखकर अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित पढ़ाई जरूरी है, दो दिन पढ़ो और दो दिन छोड़ो जैसी आदत से बचना चाहिए।

प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी किताब को 2-3 बार पढ़ना, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज सॉल्व करना फायदेमंद है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और कम से कम 5 सैंपल पेपर हल करने से परीक्षा पैटर्न की अच्छी समझ बनती है। ऑर्गेनिक में नाम रिएक्शन्स, रीजेंट्स और फ्लोचार्ट याद करने पर जोर दिया गया है, जबकि फिजिकल में न्यूमेरिकल्स की नियमित प्रैक्टिस जरूरी बताई गई है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर खास ध्यान देने की सलाह दी गई है, क्योंकि पेपर में इनकी संख्या 16 होती है।

रिवीजन स्ट्रैटजी के तहत फ्लैशकार्ड्स, माइंड मैप्स और ग्रुप डिस्कशन को प्रभावी माना गया है। साथ ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की थ्योरी और वीवा प्रश्नों की दोहराई जरूरी है। परीक्षा से पहले आखिरी हफ्ते में केवल रिवीजन और पिछले साल के प्रश्न पत्रों पर फोकस करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

परीक्षा के दौरान पेपर पैटर्न का पालन करने, पहले छोटे प्रश्न हल करने और फिर बड़े प्रश्नों पर जाने की सलाह दी गई है। साफ-सुथरी लिखावट, सही डायग्राम और रीजनिंग आधारित प्रश्नों जैसे डी और एफ ब्लॉक पर अच्छी पकड़ विद्यार्थियों को सफलता की ओर ले जा सकती है।

4 दशक पुराने हत्या के मामले में वांछित 50 हजार का इनामी गिरफ्तार

कानपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर के कर्नलगंज क्षेत्र में वर्ष 1984 में हुयी हत्या के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने यहां पत्रकारों को बताया कि 1984 में कर्नलगंज क्षेत्र में सुल्तानव्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी घटना के बाद शौकत नामक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्ष 1990 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था। अभियुक्त अदालत की पेशी में भी नहीं आ रहा था। तत्कालीन पुलिस प्रमुख ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिये 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।मौजूदा पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पुराने मामले का संज्ञान लेते हुये सर्विलांस और कर्नलगंज पुलिस की एक टुकड़ी को शौकत की गिरफ्तारी के लिये लगाया था।नतीजन आज सेन्ट्रल जोन सर्विलांस टीम और थानार्नलगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

नारदाश्रम में आयोजित भण्डारे में श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद

» श्रीमदभागवत कथा के समापन के बाद हुआ भण्डारा

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। अखंड ब्रह्मचारी नारायण स्वरूप जी महाराज की पुण्यतिथि पर इस वर्ष भी नार खास स्थित नारदाश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया । जिसमें श्रद्धालुओं ने लाइन प्रसाद ग्रहण किया। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक चलता है। जिसमें श्री राम कथा होती है। इस वर्ष वृंदावन धाम से पधारे धनंजय दास जी ने लोगों को राम कथा सुनाई। इसके साथ ही यज्ञ हुआ एवं गौ सेवा का महत्व लोगों को बताया गया। बताते चलें कि 4 फरवरी 1996 माघी पूर्णिमा को अखंड ब्रह्मचारी नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने गोलोक प्रयाण किया था। उनकी पुण्यतिथि पर तब से अब तक लगातार माघी पूर्णिमा को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है । उसी क्रम में इस वर्ष भी बसंत पंचमी से प्रारंभ हुई नव दिवसीय राम कथा के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया। रामजी तिवारी,गोपाल दीक्षित, सुनंदा जी, अविनाश तिवारी, सुदीप तिवारी, मंगलम, तेजू अवस्थी, अनंदीलाल अवस्थी, छानू तिवारी आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया।

सम्पादकीय

बजट में युवा व चुनावी राज्यों का ध्यान

राजग सरकार द्वारा रविवार को पेश आम बजट कई मायनों में खास रहा। तमिलनाडु के लोगों की आकांक्षाओं की पर्याय कांजीवरम साड़ी पहने लगातार नौवीं बार बजट पेश करके निर्मला सीतारमण ने नारी शक्ति का परचम ही लहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की दशा-दिशा पर तीन शब्दों में संदेश दिया कि यह स्किल, स्केल और सस्टेनबिलिटी का बजट है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विकास व आत्मनिर्भरता के लिए बजट है। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। आम आदमी की जिज्ञासा यही होती है कि क्या सस्ता होगा और किस पर उसकी जेब ढीली होगी। कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव्स, सोलर पैनल, चमड़ा उत्पाद, 17 दवाइयां तथा सात दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। हर बार की तरह शराब, सिगरेट व तंबाकू प्रेमियों की जेब ढीली होगी। नये प्रावधानों में विदेशों में पढ़ रहे छात्रों को भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस कम होगा। विदेश यात्रा पैकेज पर भी छूट दी गई है। आने वाले महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनका भी बजट में खास ख्याल रखा गया है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दुर्लभ रेयर अर्थ पर ध्यान केंद्रित कर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें तमिलनाडु-केरल का खास ध्यान रखा गया। आसन्न चुनाव वाले इन राज्यों के मछुआरों व नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन व छूट दी गई है। हालांकि, एसटीटी बढ़ाने के मुद्दे पर शेयर बाजार को बजट रास नहीं आया। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग में चालीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। वहीं सस्ती दवाओं के लिए 'बॉयोफार्मा शक्ति योजना' के लिए दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान होगा, जिससे देश में मधुमेह व कैंसर की सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। दूसरी ओर आसन्न चुनाव वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, असम व तमिलनाडु को हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का लाभ देने का प्रस्ताव है। वहीं असम को बौद्ध सर्किट का लाभ दिया गया है। यह योजना बौद्ध तीर्थों के विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा यहां तक कि तीर्थयात्रियों की पहुंच आसान बनाने की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर डिजिटल मनोरंजन क्रांति हेतु रचनात्मक बढ़ाने वाली 'ऑरेंज इकॉनोमी' को भी प्राथमिकता बनाया गया है ताकि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। हर बार नौकरी पेशा वर्ग की आस होती है कि इनकम टैक्स में छूट मिले। लेकिन इस बार किसी स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ। हां, अप्रैल 26 तक नया आयकर कानून लागू करने की बात बजट में कही गई है, जिसमें आयकर रिटर्न की फाइलिंग से जुड़ी समय सीमा और नियमों में बदलाव होगा। निश्चित रूप से दुनिया आपूर्ति श्रृंखला में जारी वैश्विक उथल-पुथल और टैरिफ युद्ध के बीच राजग सरकार ने आम बजट में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। साथ ही आजादी के सौ साल पूरे होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। हर बार की तरह शराब, सिगरेट व तंबाकू प्रेमियों की जेब ढीली होगी। नये प्रावधानों में विदेशों में पढ़ रहे छात्रों को भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस कम होगा। विदेश यात्रा पैकेज पर भी छूट दी गई है। आने वाले महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनका भी बजट में खास ख्याल रखा गया है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दुर्लभ रेयर अर्थ पर ध्यान केंद्रित कर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें तमिलनाडु-केरल का खास ध्यान रखा गया।

अमिताव के सृजन में कल्पना और सच का जादुई मिश्रण

यशवंत सचदेव

लेखक अमिताव घोष की नवीनतम पुस्तक 'घोस्ट आई' दिखावे से परे असीम प्रेम की गाथा है। वे ब्रह्मांड को समेटने की कोशिश करते हैं, पूर्व जन्मों को, इंसानों और गैर-इंसानों को भी। उनके लेखन की खासियत है कि वे सच और परिकल्पना को एक जादुई मिश्रण में ढाल देते हैं और उसे अपना बना लेते हैं।मेधावी लेखक अमिताव घोष इन दिनों अपनी नई किताब 'घोस्ट आई' के प्रचार लिए अपनी मातृभूमि में यात्रा कर रहे हैं, जी बिल्कुल, वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू-कश्मीर के आस-पास भी कहीं नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में साहित्य-सम्मेलनों की भरमार के बावजूद - जिसमें चंडीगढ़ में होने वाले दो सम्मेलन भी शामिल हैं, और दोनों में ध्यान ज़्यादातर इस बात पर केंद्रित रहता है कि वहां आपने किस-किस हस्ती को देखा बजाय इसके कि आपने यह वाली किताब पढ़ी है या नहीं ङ्क देश के इन हिस्सों में पाठकों का बाज़ार ज़्यादा बड़ा नहीं है। (किताबों से जुड़े लोग भी इस बारे में जानते हैं)। तो यहां अमिताव घोष के बारे में पहलू यह है - शायद वे उन सबसे ज्यादा गैर-मिलनसार लोगों में एक हैं जिनसे आपकी भेंट हुई होगी।

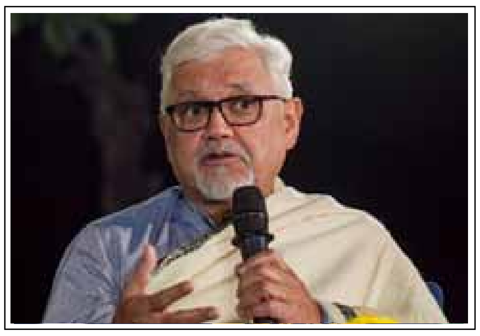

वह रूखे हैं, यहां तक कि चिड़चिड़े भी। पिछली एक किताब की बाबत एक इंटरव्यू में, उन्होंने पुस्तक के बारे में बात ही करने से मना कर दिया था। दशकों पहले मैं उनके पूर्व प्रकाशक रवि दयाल की ओर से उन्हें भेजी गई कुछ किताबों का बंडल, जो सिर्फ़ दक्षिण एशिया में छपी थीं, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क ले कर गई थी - कई ईमेल के बाद हम एक कॉफ़ी शॉप में मिले और मैंने सोचा, वाह, यहां मुझे इस मूर्धन्यता के पीछे के इंसान को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन वह शख्स अंदर आये, मुझसे किताबें लीं, हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा, मुड़े और चला गये। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी कॉफ़ी के लिए कई डॉलर ज़्यादा ही खर्च कर डाले, जो पीने में न तो गर्म थी और न ही स्वादिष्ट। बहरहाल, अगर आप जब उनका काम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत आपको 'द ग्लास पैलेस' से करनी चाहिए, एक ऐसी कहानी जो ताउम्र आपके याद रहेगी, कथानक भारत और बर्मा के बारे में है, मुश्किलों और यातनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो महान राजा थिबाव की मुसीबतों से संबंधित है, जिन्हें अंग्रेजों ने उनके प्यारे मांडले से निकालकर महाराष्ट्र के तट पर रत्नागिरी में नज़रबंद कर दिया था, जहां पर 1916 में उनकी मृत्यु एकाकीपन में हुई ङ्क सनद रहे, जहां पर 1862 में वे अपने अंतिम समय तक रहे। इन दिनों, जब चीज़ें बिखर रही हैं, तब हम भारत और उसके पूर्वी पड़ोसी म्यांमार के बीच रहे गहरे रिश्तों को भुला देते हैं। 2000 में जब अमिताव ने 'ग्लास पैलेस' लिखी और इतिहास की किताबों से इतिहास के नाटकीय पन्नों को फिर से सामने लाये, तब आप साफ तौर पर देखते कि भारत और बर्मा, दोनों देश जब ब्रिटिश राज का हिस्सा बने, अंग्रेजों ने किस प्रकार दो राजवंशों का निष्ठुरता से विनाश किया, 1935 में बर्मा के एक आज़ाद देश बनने तक, भारतीय रेलवे कोलकाता को रंगून-यांगून से जोड़ती थी और लोग बिना किसी भय या सीमा, पासपोर्ट या वीज़ा जैसी चीज़ों की अनिवार्यता बगैर एक से दूसरी जगह आते-जाते थे, काम करते थे, शादी करते थे, संतान पैदा करते थे, ठीक वैसे ही जैसा हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैले विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं और होता था; कि दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा न केवल यूरोप और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में लड़ा गया बल्कि बर्मा और मलाया भी रणक्षेत्र रहा, जिसको अब दक्षिण-पूर्व एशिया कहते हैं; और यह कि भारतीय सैनिक हर जगह लड़े, पूर्व व पश्चिम में, करीब 25 लाख सैनिक, जिनमें आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 87,000 योद्धा मारे गए- एक ऐसे देश या गठबंधन की ओर से लड़ते हुए जो उनका अपना था भी नहीं। अमिताव घोष की यही खासियत है कि वे सच और परिकल्पना को एक जादुई मिश्रण में ढाल देते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। इसलिए जब बीते हफ़्ते यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर चीन गए और आपने उनकी शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीरें देखीं, तो आपका दिमाग ज़रूर अमिताव की 'इबिस ट्रिलॉजी' की तरफ गया होगा।

बेशक, प्यार तो उन अनजानी जगहों पर भी पनप सकता है जिसके बारे में कभी सोचा न हो, क्योंकि लोगों की जीवनधारा रूपी नाटक का भव्य मंचन महाद्वीपीय सीमाओं से परे भी होता रहता है, जिसमें युद्ध, व्यापार और वह अंतिम चीज़, अफीम भी शामिल है।'रिवर ऑफ़ स्मोक' बताती है कि क्यों कई चीनी इतिहासकारों का मानना है कि वर्ष 1839 ने 'अपमान की सदी' की शुरुआत की, जो अफीम युद्धों से शुरू हुई और 1949 में खत्म हुई जब माओ ने अपने असंगठित योद्धाओं के समूह का नेतृत्व करते हुए बीजिंग के बीचों-बीच स्थित 'मध्य राजशाही' (चीन का एक अन्य नाम) का तख्तापलट कर दिया था।

आर्थिक मायने विशिष्ट, सियासी प्रभाववश विकसित भारत

यह बजट हर वर्ग

डा0 सुधीर कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सुधारों को मजबूत करने और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप करार दिया। मोदी ने कहा कि यह बजट नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है और अपार अवसर प्रदान करता है।भारत सरकार का 2026-27 का केंद्रीय बजट विकास, रोजगार सृजन और राजकोषीय अनुशासन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026, दिन रविवार को इसे संसद की पटल पर प्रस्तुत करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लिहाजा इसके आर्थिक मायने और राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। इसपर बहस तेज हो गई, जो कई कारणों से अभिप्रेरित है। जहां सत्ता पक्ष ने इसे युवा शक्ति का प्रतीक बजट ठहराया, वहीं विपक्ष ने इसे अदृश्य बजट करार देते हुए जमकर आलोचना की। जहां तक कुल बजट आकार की बात है तो यह 53.5 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। भले ही राजकोषीय घाटा जीडीपी (त्रष्ठक्क) का 4.3त्न रखा गया, जो पिछले साल के 4.4त्न की तुलना में कुछ कम है।

वहीं, जहां तक कर सुधार की बात है तो आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं आया; जबकि नया आयकर अधिनियम 2026 अप्रैल से लागू होगा। वहीं, एफ एंड ओ (स्न×ह्र) पर एसटीटी बढ़ाकर 0.05-0.15त्न किया गया, विदेशी पर्यटन/शिक्षा हेतु टीसीएस (ञ्जष्टस्) 2त्न किया गया। जहां तक बजट में क्षेत्रीय प्रावधान किये जाने की बात है तो रोजगार-एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का वृद्धि कोष प्रस्तावित है, जबकि क्रेडिट गारंटी दोगुनी की गई। वहीं, बुनियादी ढांचा हेतु 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, शहरी विकास के लिए 5,000 करोड़ प्रति वर्ष का प्रस्ताव और स्वास्थ्य-कृषि क्षेत्र में 17 कैंसर दवाएं सस्ती किये जाने की घोषणा, बायोफार्मा को 10,000 करोड़ दिए जाने का प्रस्ताव और मखाना बोर्ड मजबूत किये जाने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, अन्य महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं में

नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्यात प्रोत्साहन पर फोकस प्रदान करते हुए सुधारों का रिफॉर्म एक्सप्रेस जारी रखा गया। लिहाजा यह विकसित भारत 2047 का रोडमैप है।इन बजट प्रस्तावों के आर्थिक मायने दूरगामी महत्व वाले हैं, क्योंकि बजट में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है, वहीं, राजकोषीय घाटा 4.3त्न जीडीपी पर लक्षित है, जबकि ऋण-जीडीपी अनुपात 55.6त्न तक सुधरेगा, जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। वहीं, कर राहत जैसे टीसीएस /टैक्स सीमा बढ़ाना, एमएसएमई क्रेडिट गारंटी दोगुनी करना और स्टार्टअप फंड कंज्यूमर खर्च व निवेश को प्रोत्साहित करेगा।जहां तक बजट प्रस्तावों के राजनीतिक प्रभाव की बात है तो निश्चय ही सरकार ने रोजगार (जैसे चमड़ा क्षेत्र में 22 लाख नौकरियां), किसान योजनाएं (मखाना बोर्ड) और स्वास्थ्य (10,000 मेडिकल सीटें) पर फोकस कर एनडीए (हृष्ठ) सहयोगियों व ग्रामीण मतदाताओं को मजबूत संदेश दिया है। जबकि विपक्ष ने इसे %राजनीतिक बजट% करार दिया है, खासकर राज्य-विशिष्ट घोषणाओं पर, लेकिन विकास लक्ष्य (विकसित भारत 2047) बीजेपी की छवि को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर, यह गठबंधन स्थिरता और 2029 के आम चुनाव सहित 2026, 27 और 28 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।लिहाजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सुधारों को मजबूत करने और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप करार दिया। मोदी ने कहा कि यह बजट नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है और अपार अवसर प्रदान करता है। युवाओं के लिए नया आयाम तथा हर घर लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित करने वाला बताया। विकास फोकस करते हुए उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और समावेशी विकास का माध्यम माना, जो देश को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

विपक्ष की आलोचना के बीच सरकार की सकारात्मक छवि मजबूत करने वाला कदम है।हालांकि, भारत के 2026-27 बजट पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। विभिन्न दलों ने इसे निराशाजनक, फीका और अपेक्षाओं से कम बताया।

जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इसे ÷पूरी तरह फीका÷ कहा, जिसमें भारी माहौल के बावजूद कोई स्पष्ट आवंटन या पारदर्शिता नहीं है। जबकि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि सरकार अर्थव्यवस्था को गर्त में डुबो रही है। वहीं कांग्रेस नेता जेबी माथेर ने केरल के लिए इसे निराशाजनक बताया है। वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि के लिए कुछ नहीं है। जबकि सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे गरीब-किसान-युवा विरोधी बजट बताया।

मकनपुर मेला: सूफी परंपरा और साझा विरासत का दिखा इतिहास

दरगाही साहिर हुसैन जाफरी की पुस्तक 'इतिहास के आईने में मकनपुर' भेंट

➪ दरगाह जिंदा शाह मदार पहुंचकर अफसरों ने जाना सदियों पुराना इतिहास

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। सदियों से गंगा-जमुनी तहज़ीब, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल बने मकनपुर के ऐतिहासिक बसंत मेले ने एक बार फिर अपनी विरासत का साक्षात्कार कराया। रविवार को सीबीसीआईडी के एडिशनल एसपी मुकेश प्रताप सिंह और फर्रुखाबाद के वन रेंजर अनूप कुमार ने मेले में शिरकत कर सूफ़ी परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर को नजदीक से देखा।

तहसीलदार अनुभव चंद्रा के साथ दरगाह ज़िंदा शाह मदार पहुंचे अफसरों का मेला खजांची, मेला कमेटी सदस्य साहिर हुसैन, चांदी भाई सहित दरगाही पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दरगाह परिसर में प्रवेश करते ही प्राचीन द्वार और उस पर उकेरी गई अरबी नक्काशी ने अफसरों का ध्यान खींचा। उन्होंने दरगाहियों से शिल्पकला और दरगाह के ऐतिहासिक महत्व की विस्तृत जानकारी ली।

इसके बाद सदर परिसर में दरगाहियों द्वारा पगड़ी बांधकर अफसरों का सम्मान किया गया। अफसरों ने दरगाह पर माथा टेक कर अमन-चैन की दुआ मांगी और कहा कि ऐसे ऐतिहासिक मेले सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के साथ-साथ साझा सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखते हैं। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं और अनुशासन की भी सराहना की।

अफसरों की ऐतिहासिक रुचि को देखते हुए ग्राम प्रधान मजाहिर हुसैन ने दरगाही साहिर हुसैन जाफ़री द्वारा लिखित पुस्तक 'इतिहास के आईने में मकनपुर' भेंट की। पुस्तक में ज़िंदा शाह मदार, उनकी दरगाह, बसंत मेले की परंपरा और स्वाधीनता आंदोलन में इस सूफ़ी सिलसिले की भूमिका का विस्तार से उल्लेख है। अफसरों ने पुस्तक को अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए पुनः आने का आश्वासन दिया।

थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं के आने से मेले में चढ़ा अंतरराष्ट्रीय रंग

गत सप्ताह ऐतिहासिक मकनपुर बसंत मेले में थाईलैंड से आए लगभग दो सौ बौद्ध भिक्षुओं के काफिले ने मेले को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। एक समान वस्त्रों में पदयात्रा करते हुए भिक्षु मेले तक पहुंचे और ईशन नदी के तट पर अस्थायी शिविर लगाया। उन्होंने सूफ़ी परंपराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को नजदीक से देखा। भिक्षुओं की मौजूदगी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई तरह के दावे सामने आए। हालांकि, एक ब्लॉगर से बातचीत में भिक्षुओं ने स्पष्ट किया कि वे थाईलैंड से कोलकाता होते हुए मकनपुर पहुंचे हैं। विदेशी मेहमानों की शिरकत से मेले की रौनक और बढ़ गई तथा जायरीनों में विशेष उत्सुकता देखी गई। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश कालीन इतिहासकारों और विभिन्न धर्मगुरुओं की रचनाओं में ज़िंदा शाह मदार और बसंत मेले का उल्लेख मिलता है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी को धार्मिक संवाद और सांस्कृतिक सेतु के रूप में देखा जा रहा है।

मकनपुर बसंत मेले का समापन कल

17 जनवरी से शुरू हुआ ऐतिहासिक मकनपुर बसंत मेला मंगलवार को अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा। औपचारिक समापन मेला तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। इस अवसर पर मेले के सफल आयोजन में योगदान देने वाले मेला कमेटी के सदस्यों और मेले में तैनात प्रशासनिक टीम को सम्मानित किया जाएगा। समापन समारोह को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

वसूली कांड में शिकंजा, मेला कमेटी के दो सदस्य रडार पर

बिल्हौर (कानपुर)। मकनपुर के बसंत मेले में अवैध वसूली के आरोपों में मेला कमेटी के दो सदस्य तहसील प्रशासन के रडार पर आ गए हैं। कमेटी के भीतर चल रही गुटबाज़ी के चलते दुकानदारों और पशु व्यापारियों से वसूली से जुड़े पुख्ता इनपुट प्रशासन तक पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विरोधियों को फंसाने के लिए कुछ सदस्यों द्वारा भ्रामक सूचनाएं देने की भी शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच चल रही है। तहसील प्रशासन ने पूरे मामले की क्रॉस-वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। प्रशासनिक संकेत साफ हैं कि दोष सिद्ध होने पर संबंधित सदस्यों पर आपराधिक मुकदमे, कमेटी से निष्कासन और मेले से बेदखली जैसी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही गलत सूचना देने वालों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। मेले की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के लिए प्रशासन का संदेश स्पष्ट है बख्शा कोई नहीं जाएगा।

नाबालिग किशोरी के अपहरण का केस दर्ज

बिल्हौर(कानपुर)। शिवराजपुर थाना क्षेत्र से लापता 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के मामले में पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ अपहरण सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए हैं। बताया गया है कि किशोरी 16 जनवरी की रात घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने शिवराजपुर थाने में तहरीर दी गई। परिजनों ने गांव के ही युवक अंकुर पर किशोरी को फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा।

रविदास जयंती पर समरसता और समानता का संदेश दिया

बिल्हौर(कानपुर)। संत शिरोमणि रविदास की जयंती के अवसर पर दिलीप नगर स्थित कार्यालय में समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सपा विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का रास्ता दिखाया। उन्होंने भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाकर समतामूलक समाज की परिकल्पना की। आज के समय में उनके विचार समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य कार्तिकेय शुक्ला समेत सपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

संघ शताब्दी वर्ष पर हिंदू सम्मेलन में पंच प्रणों को अपनाने का लिया संकल्प

➪ राष्ट्र निर्माण में सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और संस्कारों की निर्णायक भूमिका होती

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को बापू गेस्ट हाउस, बिल्हौर में हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ वरिष्ठ स्वयंसेवक रामकुमार गुप्ता एवं विभाग प्रचारक द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

फर्रुखाबाद विभाग के विभाग प्रचारक राहुल ने प्रबोधन करते हुए भारत के गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों के त्याग-बलिदान और संघ की सौ वर्षों की राष्ट्रसेवा यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और संस्कारों की निर्णायक भूमिका होती है। उनके संबोधन से पूरे सभागार में राष्ट्रभक्ति और दायित्वबोध का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

पंच प्रणों को जीवन में उतारने का संकल्प

प्रबोधन सत्र के उपरांत उपस्थित हिंदू समाज ने संघ के पंच प्रण सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण, नागरिक कर्तव्य को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम के प्रारंभिक सत्र में नगर के कथावाचक पं. कृष्ण मोहन शास्त्री ने हिंदू समाज की एकता और अखंडता पर विचार व्यक्त किए। जीपीआरडी पटेल महाविद्यालय के शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता रमाकांत कटियार ने पर्यावरण संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता बसंती सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे, जबकि समाजसेवी परमसुख जी ने प्रेरक संबोधन से उपस्थित जनसमूह को मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ स्वयंसेवक जयप्रकाश कुशवाहा ने किया। सम्मेलन में जिला प्रचारक धीरेंद्र जी, सेवा प्रमुख संदीप, अतुल तिवारी, जिला सद्भावना प्रमुख नमो नारायण दीक्षित, तुषार मिश्रा, सचिन गौतम, राहुल पांडे, दुर्गेश कुशवाहा, रामजी गुप्ता, वाहिनी बस्ती के बस्ती प्रमुख आशुतोष त्रिपाठी, अभिजीत मिश्रा, कुश मिश्रा, सह नगर कार्यवाहक अश्वनी, संदीप अवस्थी, राहुल, अमित मिश्रा, अतुल सांवरे तथा सेठ रामकुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं नागरिक उपस्थित रहे।

बिना परमीशन मशाल जुलूस निकालने पर पुलिस सख्त

» युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत 23 नामजद, 6-7 अज्ञात पर दर्ज की गई एफआईआर

» आग लगने के खतरे से दुकानदारों में दहशत, कई दुकानों के शटर गिरे, भगदड़ के हालात बने

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। पुलिस के खिलाफ बिना अनुमति रात में मशाल जुलूस निकालने के मामले में मऊ दरवाजा थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव समेत 23 नामजद और 6-7 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस के अनुसार, टाउन हॉल से तिकोना चौकी तक निकाले गए मशाल जुलूस के दौरान मुख्य मार्गों पर नारेबाजी की गई, जिससे मार्गों पर अफरातफरी मच गई।

जुलूस में जलती मशालों के कारण आग लगने का खतरा पैदा हुआ और दुकानदारों में दहशत फैल गई। कई दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दीं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और किसी बड़े हादसे की आशंका उत्पन्न हो गई।

इन पर दर्ज हुआ मुकदमा

अंकुर श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह चौहान, अंजुम उर्फ अंजुम, रोहन कश्यप, गोविंद बाथम, मुनव्वर, अनमोल, जय कश्यप, सचिन, अजीम, करीम, वाजिद अली, कमल, आदित्य श्रीवास्तव, हनी, जतिन, जीतू श्रीवास्तव सहित कुल 23 नामजद व 6-7 अज्ञात। थाना मऊ दरवाजा के उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है।

- ➪ बिना अनुमति निकाला गया मशाल जुलूस
- ➪ मुख्य मार्गों पर नारेबाजी से अफरातफरी
- ➪ आग व भगदड़ की आशंका
- ➪ 23 नामजद, 6-7 अज्ञात पर एफआईआर
- ➪ मऊ दरवाजा थाना पुलिस कर रही जांच

घाटमपुर में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान

गांव-गांव चौपाल लगाकर ग्रामीणों को किया जागरूक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के देशव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण ने घाटमपुर क्षेत्र में गांव-गांव चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद शुरू कर दिया है। जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए मनरेगा को बचाने का संकल्प दिलाया।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि वर्ष 2006 में यूपीए सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों के लिए रोजगार की गारंटी योजना लागू की गई थी, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के नाम से जाना जाता है। यह योजना ग्रामीणों के जीवन-यापन में बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हुई थी।

कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजीआरएएमजी योजना कर दिया है, जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इसी क्रम में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के पतारा ब्लॉक के दतारी और सरगंवा गांवों में किसान-मजदूरों के साथ चौपालें लगाकर मनरेगा और नई योजना के बीच का अंतर समझाया गया।

इस दौरान जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि सरकार मनरेगा को कमजोर कर गांव के मजदूरों और किसानों को फिर से पूंजीपतियों पर निर्भर बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे किसान-मजदूर विरोधी मंसूबों को सफल नहीं होने देगी।

चौपाल की संयोजिका उषा रानी कोरी ने कहा कि यह एक जनांदोलन है, जिसमें ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है, लेकिन ग्रामीणों को भी

आगे आकर साथ देना होगा।

मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के समन्वयक आनंद वर्मा ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग अब मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से जागरूक होकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की।

चौपालों में शक्ति पांडेय, अवधेश कमल, मोहम्मद शकील, रामचंद्र सचान, अलकेश शुक्ला, सोनू कमल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।

गंगा के कटान से कटरी भीमपुर-धर्मपुर में दर्जनों मकान गंगा में समाए

» खेत जलमग्न, ग्रामीणों में दहशत, तटबंध समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। सदर विधानसभा क्षेत्र के कटरी भीमपुर और कटरी धर्मपुर गांवों में गंगा नदी के भीषण कटान ने भारी तबाही मचा दी है। कटान की चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक मकान गंगा में समा गए, जबकि सैकड़ों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। हालात बिगड़ते देख गांवों में हड़कंप मचा हुआ है।कटान की गंभीर स्थिति को लेकर तटबंध समिति के अध्यक्ष भइयन मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल राहत व बचाव कार्य की मांग की। तटबंध समिति अध्यक्ष भइयन मिश्रा ने बताया कि कटान के कारण न सिर्फ लोगों के घर उजड़ गए हैं, बल्कि पशु, अनाज और रोज़गार का साधन भी खतरे में पड़ गया है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और भयावह हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आपदा राहत घोषित कर स्थायी समाधान की मांग की है।

ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें

- ➪ गंगा के तेज कटान को रोकने के लिए तत्काल तटबंध निर्माण
- ➪ कटान से बेघर हुए परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था
- ➪ डूबे मकानों में रखा राशन, घरेलू सामान और पशुओं के लिए सहायता
- ➪ फसल नष्ट होने पर किसानों को मुआवजा देने की मांग

कानपुर-प्रयागराज के बीच परीक्षा विशेष ट्रेनों ने दी राहत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रयागराज मंडल ने कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज जंक्शन के बीच दो परीक्षा विशेष ट्रेनों का संचालन किया। यह व्यवस्था आरओ परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन राहत रही। । मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के निर्देशन एवं उप मुख्य यातायात प्रबंधक कानपुर आशुतोष सिंह के मार्गदर्शन में वाणिज्य विभाग, आरपीएफ एवं जीआरपी की संयुक्त टीमों ने स्टेशन परिसर में भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पहली विशेष ट्रेन दोपहर 1:35 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 6 से रवाना हुई, जबकि दूसरी ट्रेन सायं 6 बजे तक उपलब्ध कराई गई। विशेष ट्रेनों से परीक्षार्थियों को राहत मिली और भीड़ नियंत्रण में सहायता हुई।

मन की शुद्धि के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक

त्रिपुरारी धाम गिरदौ में कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा विकासखंड के त्रिपुरारी धाम गिरदौ में रविवार को नव दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में पीले वस्त्र धारण किए कन्याएं एवं महिलाएं सिर पर कलश लेकर मंगलगीत गाती हुई चल रही थीं। कलश यात्रा में गाजे-बाजे के साथ जय श्री राधे, जय श्रीकृष्ण एवं देवी-देवताओं के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। यात्रा में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे बच्चे, युवतियां एवं महिलाएं शामिल हुईं। कलश यात्रा के उपरांत कथावाचक अनुज आचार्य शास्त्री द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के प्रथम दिवस उन्होंने कहा कि मनुष्य तन का स्नान तो विभिन्न साधनों से कर लेता है, किंतु मन की शुद्धि के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद्भागवत कथा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और मन को शांति प्राप्त होती है। कथा आयोजन में परीक्षित कस्तूरी देवी एवं जगनायक सिंह राठौर रहे, जबकि कार्यक्रम का आयोजन टिंकू सिंह राठौर द्वारा किया गया। इस मौके पर संजू यादव, प्रदीप कश्यप, शिव नारायन, पूर्व प्रधान लक्ष्मी नारायण, सुनील सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण, श्रद्धालु एवं भक्तजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 232 मरीजों को मिला इलाज

» जिला मलेरिया अधिकारी ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के देवीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न रोगों से पीड़ित कुल 232 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें नि:शुल्क दवाएं बांटी की गईं।

बरौर कस्बा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 88, मलासा में 66 तथा जरसेन में 78 मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया गया। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी मारुति दीक्षित ने बरौर एवं मलासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर साफ-सफाई एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. विकास ने लोगों को मौसम परिवर्तन के दौरान स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए कहा।

स्वास्थ्य मेले में डॉ. शशि, डॉ. रुचि श्रीवास्तव, डॉ. आफताब आलम, फार्मासिस्ट सुधीर कुमार, फार्मासिस्ट अनिल कुमार, त्रिलोकी नाथ, एलटी शिवम, योगेंद्र सिंह, फहीम, दिव्यांशी, राम प्रताप, संगिनी रीता, ललिता, सुरेश कुमार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

आस्था, व्यवस्था और स्वच्छता का संगम

6 फरवरी से पूर्व कालेश्वर धाम में चला विशेष स्वच्छता अभियान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ग्राम पंचायत गजनेर स्थित प्राचीन कालेश्वर मंदिर में 6 फरवरी से प्रस्तावित विशाल यज्ञ व भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य रास लीलाओं के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

ग्राम प्रधान अनीशा बेगम व उनके पति मो. फिरोज की देखरेखमें मंदिर परिसर सहित संपर्क मार्गों पर व्यापक स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण अभियान संचालित कराया गया।

यज्ञ आयोजन से पूर्व कालेश्वर मंदिर परिसर, प्रवेश द्वार एवं मुख्य मार्गों पर साफ-सफाई कराऊ जा रही है। साथ ही मार्ग को व्यवस्थित किया जा रहा है। मंदिर के महंत ने कहा कि ग्राम प्रधान एवं उनके सहयोगियों की यह सक्रियता धार्मिक आयोजनों की सफलता के साथ-साथ सामाजिक चेतना और जनसेवा की भावना को भी सुदृढ़ करती है।

दुष्कर्म के मामले में फरार दो शातिर गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना गजनेर पुलिस ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त विनोद उर्फ सनोज उर्फ शरद कुमार निवासी ग्राम बलवां तराव, जनपद गाजीपुर को रनियांङ्कसरवनखेड़ा मार्ग से गिरफ्तार किया गया। वहीं, अमन यादव निवासी ग्राम रतवा, गजनेर को रामपुर-करसा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में विवेचना के दौरान बीएनएस की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई थीं।

सपा की नीतियों का प्रचार करने निकले बेरिया

विधानसभा चुनाव को लेकर गोटियां बिछाने में जुटे दिग्गज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। विधानसभा चुनाव भले ही अभी एक वर्ष दूर हो लेकिन रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में हलचल इन दिनों तेज हो गई है। जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार मैदान में कूदते दिखाई दे रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी से शिवकुमार बेरिया भी पार्टी की नीतियों का प्रचार-प्रसार कर दम भर रहे हैं।

भीतरगांव कुर्सी खेड़ा में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी व पूर्व विधायक शिवकुमार बेरिया ने कार्यकर्ताओं संग गोष्ठी की। इस दौरान शिवकुमार बेरिया ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवकुमार बेरिया ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने समाज को बांट कर रख दिया।

देश की पूंजी का 90 फ़ीसदी 10त्न आबादी के पास है जबकि 90त्न आबादी के पास महज 10 फ़ीसदी पूंजी है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सूबे से भाजपा का सूपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी की विकास वाली सरकार बनेगी।

जिला उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान ने कहा कि कार्यकर्ता नये मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास करते रहें। सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा, पूर्व जिलाध्यक्ष लाखन सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष गोपाल गुप्ता, धर्मेंद्र त्रिवेदी, विपिन शुक्ला, सौरभ यादव , वीरू कुशवाहा, राजेंद्र बहादुर राजपूत सहित कई सपाई मौजूद रहे।

20 साल से बनने के इंतजार में बटपरू गाँव की मेन रोड

विकास की आस में तरस गई ग्रामीणों की आंखें

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त प्रदेश होने की बात कर रही है और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सड़कों का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कई जगहों पर कुछ अलग है। बटपरू गाँव के लोगों को अपने गांव के लिए जाने वाले मुख्य डामर रोड के बनने का बीते 20 वर्षों से इंतजार है लेकिन किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने उनके दर्द को न सुना। उखड़ी सड़क और गड्ढों से होकर ग्रामीणों का आवागमन हो

रहा है।जनपद की रसूलाबाद तहसील से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बटपरू गांव बदहाली के आंसू बहा रहा है।20 वर्षों में चार विधानसभा और चार लोकसभा के चुनाव हो चुके हर चुनाव में बटपरू गांव के लोगों को केवल वादे मिले। जो भी प्रत्याशी गांव वोट मांगने पहुंचे जीतने के बाद उसने गांव की सुध नहीं ली।

बिल्हौर- इटावा संपर्क मार्ग से बटपरू को जाने वाला डामर मार्ग महज 1 किमी लंबा है। बटपरू गांव को जाने के लिए यह मुख्य मार्ग है। जहां से प्रतिदिन सैकड़ो लोगों का आवागमन होता है लेकिन डामर रोड से डामर व गिट्टी गायब होती जा रही है। जिससे सड़क पर चलना अब दूभर हो गया है और हादसों से खाली नहीं है। यहां के रहने वाली श्री कृष्णा, रामकिशन,मोनू , धर्मवीर, कुलदीप, गोविंद, सीपू, प्रमोद आदि ने बताया कि उनके गांव के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि विधानसभा चुनाव से पहले उनके गांव को जाने वाले इस मुख्य मार्ग का निर्माण न हुआ तो पूरे गांव के लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे।

क्या बोले जिम्मेदार

इस संबंध में क्षेत्रीय सदस्य जिला पंचायत जनार्दन सिंह ऋषि से बात की तो उन्होंने बताया कि बड़ी रोड है और स्टेट हाईवे से उसका संपर्क है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसको लेकर जिम्मेदारों को प्रस्ताव भेजा गया है।

अकबरपुर में संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम आयोजित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात. रविवार को अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के शंकर दयाल नगर स्थित कबीर विद्यालय प्रांगण में महामना संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संत रविदास के विचारों और सामाजिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई।

अकबरपुर नगर पंचायत के सभासद प्रतिनिधि बबलू भारती ने संत रविदास के प्रसिद्ध प्रसंग मन चंगा तो कठौती में गंगा का उल्लेख करते हुए कहा कि संत रविदास मध्यकालीन भारत के महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म वर्ष 1388 में हुआ था। उनके पिता का नाम संतो राव दास और माता का नाम कलसा देवी था। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में जन्मे संत रविदास ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से छुआछूत और जातिवाद का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने बताया कि संत रविदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। संत रविदास ने बेगमपुरा नामक एक आदर्श समाज की परिकल्पना की थी, जहां कोई दुखी न हो, छुआछूत न हो, सभी समान हों, कोई भूखा न रहे और भाईचारे की भावना बनी रहे। इस अवसर पर उनके विचार ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सवन को अन्न, छोट बढ़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न को भी स्मरण किया गया।

कार्यक्रम में बबलू भारती, सभासद शिव सिंह नायक, सभासद सुनील राजपूत, सरदार प्रमोद सिंह केसावत जिला अध्यक्ष सुभासपा, सभासद आदेश यादव, हाजी मोहम्मद अबरार, रमेश नायक, संतोष बंजारा, संतोष कुशवाहा, शिव कुमार कठेरिया, जयराम गौतम, बच्चा दिवाकर, महेंद्र सिंह बंजारा सहित अन्य लोगों ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

शाम तक 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया गंगा मैया में स्नान

माघ मेला की सुरक्षा अभेद्य

कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी करते रहे सीपी जोगेंद्र कुमार

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

प्रयागराज।आप सभी को बताते चले कि प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णमा के दृष्टिगत आ रही करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करना और उन्हें सकुशल स्नान कराना किसी चैलेंज से कम नहीं था।इसी के चलते रविवार को तेजतर्रार पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार द्वारा माघ मेला क्षेत्र में बने कन्ट्रोल रूम के जरिये आरटी सेट माघ मेले में तैनात समस्त पुलिस बल को सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश व भ्रमणशील रहकर निगरानी करते नजर आए.

पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने माघ मेला में ड्यूटीरत पुलिस बल को निर्देशित किया कि वे श्रद्धालुओं के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार रखते हुये सेवा एवं समर्पण भाव से कार्य करें एवं ड्यूटी में किसी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाये।सहायक पुलिस आयुक्त तथा थाना प्रभारियों को मेला क्षेत्र में बैरीकेडिंग पर तैनात पुलिस बल की लगातार ब्रीफिंग और अटेंडेंस हेतु निर्देशित

किया।साथ ही घाटों पर तैनात पुलिस बल को श्रद्धालुओं को घाटों से लगातार मूवमेंट कराने हेतु और माघ मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों,स्नान घाटों,चौराहों व तिराहों एवं संवेदनशील स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए सतर्क निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने शनिवार देर रात्रि से ही संगम नोज पर डटे रहे और मेला क्षेत्र में बने कन्ट्रोल रूम में पल-पल की जानकारी लेते रहे।साथ ही सुरक्षा व्यवस्था,भीड़ प्रबंधन,यातायात संचालन,आपातकालीन योजनाओं तथा ड्यूटी प्वाइंट्स की संवेदनशीलता के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश देते रहे।बता दे कि पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होने देना चाहिते थे.इसी को लेकर वह स्वयं देर रात्रि तक मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संगम घाट,झूसी घाट,किला घाट,अरेल घाट सहित विभिन्न प्रमुख घाटों निरीक्षण कर साधु-संतों,धर्माचार्यों,कल्पवास हेतु पधारे साधकों एवं श्रद्धालुओं की आवाजाही,भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लेते रहे.वही रविवार प्रातः काल से लेकर देर रात्रि तक धर्म,आस्था और संस्कृति की संगम स्थली तीर्थराज प्रयाग स्थित पुण्य त्रिवेणी में लगभग 2.1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर भारत की अखंड शाश्वत सनातन परंपरा को नमन किया।

कलराज मिश्र की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के मायने क्या हैं?

यूजीसी नियमों के खुलेआम विरोध के बीच और ब्राह्मण संगठन तक की इनसाइड स्टोरी

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर सवर्ण नेता चुप्पी साधे रहे, उसी समय हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र खुलकर सामने आए। उन्होंने न सिर्फ इन नियमों का विरोध किया, बल्कि इन्हें वापस लेने की मांग भी की। यहीं से राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा ने जन्म लिया–क्या कलराज मिश्र एक बार फिर सक्रिय राजनीति की ओर लौट रहे हैं?

सामान्य तौर पर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद से मुक्त होने के बाद नेता सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन कलराज मिश्र इस परंपरा से अलग राह पर चलते दिख रहे हैं।

नवंबर 2025 में राज्यपाल पद से हटते ही उन्होंने 'विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद' नाम से एक संगठन का गठन किया। इसके बाद दिसंबर में दिल्ली में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देशभर के ब्राह्मण प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस संगठन के जरिए कलराज मिश्र न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में रहने वाले ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मेलन में पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी ने इस मंच को और राजनीतिक वजन दिया। इसके बाद यूजीसी नियमों का मुद्दा सामने आया तो कलराज मिश्र ने सबसे मुखर स्वर में सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मणों का पक्ष रखा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सक्रियता यूं ही नहीं है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली रहे हैं। वह दो बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा शिक्षा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। एक दौर में पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनकी पहचान थी। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता।

इसके बाद उनका लोकसभा टिकट काटकर उन्हें पहले हिमाचल प्रदेश और फिर राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। उस समय यह माना गया कि अब वह सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे।

लेकिन राज्यपाल पद से हटते ही जिस तरह से उन्होंने सामाजिक संगठन खड़ा किया और संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बयान दिए, उसने इस धारणा को बदल दिया है।

हालांकि चुनावी राजनीति में उनकी सीधी वापसी की संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन यह भी सच है कि उनका राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनके पुत्र अमित मिश्र प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कलराज मिश्र खुद चुनाव न लड़ें, लेकिन ब्राह्मण समाज के एक बड़े चेहरे और दबाव समूह के रूप में अपनी भूमिका फिर से स्थापित करना चाहते हैं।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, पार्टी के भीतर ब्राह्मण नेतृत्व की कमी और सवर्ण समाज में बढ़ती असंतुष्टि के बीच कलराज मिश्र खुद को एक वैचारिक और सामाजिक नेतृत्व के रूप में सामने ला रहे हैं। यूजीसी नियमों का विरोध इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, कलराज मिश्र की मौजूदा सक्रियता को सिर्फ सामाजिक संगठन तक सीमित मानना भूल हो सकती है। यह एक सोची-समझी राजनीतिक वापसी है, जो सीधे सत्ता की बजाय समाज और संगठन के रास्ते प्रभाव कायम करने की कोशिश नजर आती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह पहल भाजपा की आंतरिक राजनीति और सवर्ण समीकरणों को किस दिशा में ले जाती है।

अटल खेल महोत्सव बना दंगल

प्राइजमनी और पदकों को लेकर खिलाड़ियों का हंगामा

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित अटल खेल महोत्सव का समापन विवादों के साए में हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन प्राइजमनी और पदकों के वितरण को लेकर खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच देर शाम तक तीखी नोकझोंक होती रही, जिसे काफी मशक्कत के बाद शांत कराया गया।

खिलाड़ियों का आरोप है कि आयोजकों ने पूर्व में घोषित की गई प्राइजमनी के अनुसार धनराशि का वितरण नहीं किया। इसके साथ ही, उन्होंने पदकों के वितरण में धांधली और हेरफेर के गंभीर आरोप भी लगाए। कई विजेताओं का कहना था कि उन्हें अब तक उनके पदक प्राप्त नहीं हुए हैं। क्रीड़ा भारती (लखनऊ) के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घोषणा के अनुरूप ही पुरस्कार राशि वितरित की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि पदकों के वितरण में कोई तकनीकी त्रुटि हुई है, तो उसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा और सभी पात्र विजेताओं को उनके पदक दे दिए जाएंगे।

भाई माफिया, अफसर कटघरे में!

अयोध्या से पूरे सिस्टम पर उठे सवाल

» इस्तीफा, सर्टिफिकेट और साजिश की परतों में उलझा जीएसटी उपायुक्त प्रकरण

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या इन दिनों सिर्फ आस्था और विकास के कारण नहीं, बल्कि एक बड़े प्रशासनिक विवाद को लेकर भी चर्चा में है। जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह का अचानक दिया गया इस्तीफा, फिर उसकी वापसी और उससे जुड़े पारिवारिक व कानूनी विवाद अब गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ओर अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बिना किसी दबाव के इस्तीफा वापस लिया है, वहीं दूसरी ओर घटनाक्रम कई अनसुलझे रहस्यों की ओर इशारा कर रहा है।

प्रशांत कुमार सिंह ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उनका भाई विश्वजीत सिंह मऊ के कुख्यात मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़ा रहा है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भाई ने उनके माता-पिता पर हमला किया था और जबरन वसूली जैसे मामलों में लिप्त रहा है। अधिकारी का कहना है कि उन्हीं के भाई ने उन्हें बदनाम करने और दबाव में लाने की साजिश रची।शंकराचार्य विवाद के बाद प्रशांत कुमार सिंह ने अचानक इस्तीफा दिया था, जिसे कुछ ही दिनों बाद वापस ले लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह स्वैच्छिक था। हालांकि प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या यह फैसला वास्तव में बिना किसी दबाव के लिया गया, या इसके पीछे कोई और वजह थी।

जानबूझकर बदनाम किया जा रहा

प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सच्चाई अंततः सामने आएगी। जीएसटी उपायुक्त से जुड़ा यह प्रकरण अब अयोध्या का सबसे चर्चित प्रशासनिक मामला बन चुका है।

स्वराज इंडिया FOLLOW UP

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू विकलांगता प्रमाण पत्र से जुड़ा है। आरोप लगाया गया कि यह प्रमाण पत्र फर्जी है। इस पर प्रशांत सिंह का कहना है कि यह प्रमाण पत्र सीएमओ कार्यालय से विधिवत जारी हुआ था और जांच में इसे सही पाया गया। उन्होंने बताया कि अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में भी प्रमाण पत्र को वैध माना गया। इसके बावजूद इसे बार-बार फर्जी बताकर विवाद खड़ा किया जा रहा है।

प्रमाण पत्र मामले में सीएमओ मऊ कार्यालय की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पहले जांच के आदेश, फिर प्रमाण पत्र को सही ठहराने से स्थिति और उलझ गई है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में स्पष्ट और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है, ताकि संदेह की स्थिति समाप्त हो सके।

पैसे दो, तभी होगा आंकलन!

» निपुण परीक्षा में वसूली का खेल, बच्चों पर दबाव

» शिक्षिका ने प्रशिक्षुओं पर लगाया गंभीर आरोप

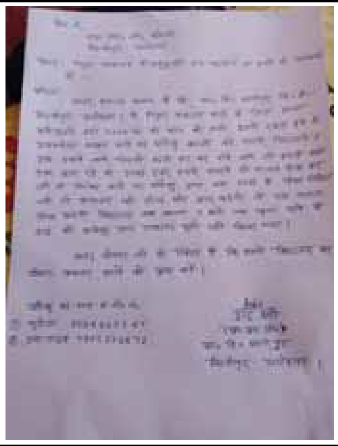

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में चल रहे निपुण आंकलन को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा शिक्षकों से अवैध धन उगाही का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए विकास खंड मिल्कीपुर के प्राथमिक विद्यालय मांगीपुर की प्रभारी प्रधानाध्यापिका इन्दू वर्मा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है।प्रधानाध्यापिका इन्दू वर्मा ने एसआरजी मिल्कीपुर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनके विद्यालय में निपुण आंकलन के लिए डायट अयोध्या से आई दो प्रशिक्षु गुड़िया और उमा यादव ने आंकलन करने के बदले 5 हजार रुपये की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने में असमर्थता जताई, तो प्रशिक्षुओं का व्यवहार आक्रामक हो गया। आरोप है कि इसके बाद प्रशिक्षुओं ने बच्चों को डांटना, चिल्लाना और उनका हाथ दबाना शुरू कर दिया, जिससे बच्चे डरकर रोने लगे। इतना ही नहीं, जो बच्चे सही उत्तर दे रहे थे, उनके जवाब भी जानबूझकर गलत चिन्हित किए गए। प्रधानाध्यापिका ने विरोध किया तो प्रशिक्षुओं ने कथित रूप से कहा कि पैसे देने पर ही सही आंकलन होगा, अन्यथा या तो आंकलन नहीं होगा या सभी उत्तर गलत कर दिए जाएंगे।शिकायत में यह भी बताया गया है कि शाम पांच बजे तक विद्यालय खुले रहने के बावजूद प्रशिक्षुओं ने आंकलन पूरा नहीं किया, जिससे बच्चों और शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है और दोषियों पर कब शिकंजा कसता है। हालांकि इस सम्बंध में बीएसए से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर की सूचना दे रहा था।

बजट में अयोध्या को बड़ी सौगात

टेंपल टाउन योजना में शामिल मिलेंगे करीब 200 करोड़

» बजट से अयोध्या में आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार: महापौर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। केंद्रीय बजट में रामनगरी अयोध्या को बड़ी सौगात मिली है। मंदिरों के शहर (टेंपल टाउन) योजना में अयोध्या को शामिल करते हुए केंद्र सरकार ने पांच वर्षों के लिए 25 शहरों के विकास हेतु 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत अयोध्या को लगभग 200 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है, जिससे शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दीपोत्सव, चौदह कोसी व चौरासी कोसी परिक्रमा जैसे आयोजनों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे शहर की व्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ता है। ऐसे में यह बजट प्रावधान अयोध्या के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

वर्तमान में शहर के कई इलाकों में ड्रेनेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। कई कॉलोनियां बिना लेआउट पास कराए विकसित हुई हैं, जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। नगर निगम क्षेत्र में शामिल ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाइट की समस्या गंभीर बनी हुई है, जबकि कैंट क्षेत्र में अब तक बिजली के तार भूमिगत नहीं हो सके हैं।

महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि पुनरुद्धार योजना के तहत मिले 45 करोड़ रुपये से विकास कार्य चल रहे हैं और जल्द ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत 20 करोड़ रुपये और मिलेंगे। अब टेंपल टाउन योजना के तहत मिलने वाली राशि से विकास को नई गति मिलेगी। महापौर ने कहा कि इस बजट से अयोध्या में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर की सकारात्मक छवि देश-विदेश में स्थापित होगी। उन्होंने अयोध्या को योजना में शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। बजट की इस सौगात से रामनगरी के सर्वांगीण विकास की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं।

गंगा-सतलज एक्सप्रेस को 5 मिनट तक रोका गया

» गोसाईगंज रेलवे फाटक पर पुलिस-गेटमैन विवाद बनी वजह

» आरोप सही मिले तो दारोगा के खिलाफ होगी कार्यवाही: सीओ सदर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग संख्या-94 पर शनिवार शाम करीब 4¬45 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब डाउन गंगा-सतलज एक्सप्रेस (3308 डाउन) के आगमन के दौरान रेलवे फाटक बंद करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान ट्रेन को स्टेशन पर करीब पांच मिनट तक रोकना पड़ा।स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रेन के आने की सूचना मिलते ही गेटमैन अशोक कुमार यादव रेलवे फाटक बंद कर रहे थे। इसी दौरान सिविल पुलिस में तैनात उप निरीक्षक कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे। आरोप है कि दोनों

के बीच कहासुनी हो गई, जिससे फाटक बंद करने में बाधा उत्पन्न हुई और ट्रेन समय पर आगे नहीं बढ़ सकी।घटना के समय रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के आरक्षी नरेश कुमार रेलवे फाटक पर यातायात नियंत्रण की ड्यूटी पर तैनात थे। विवाद बढ़ने के कारण ट्रेन को कुछ देर तक स्टेशन पर रोके रखना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक महेंद्र नाथ ने बताया कि गेटमैन की सूचना पर पूरे प्रकरण की लिखित जानकारी रेलवे विभाग की ओर से कोतवाली गोसाईगंज को दे दी गई है। वहीं उप निरीक्षक कमलेश पासवान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस समय रेलवे फाटक खुला हुआ था और वहां ई-रिक्शा, स्कूली वाहन व आम लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से फाटक खाली कराकर ट्रेन को पास कराने के लिए कहा गया था। इसी दौरान गेटमैन से कहासुनी हो गई, जिसके चलते ट्रेन कुछ देर के लिए विलंबित हुई।

> पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
>
> **अरविंद सोनकर**
> **क्षेत्राधिकारी सदर**

केंद्रीय बजट में यूपी को तोहफों के ढेर

4.26 लाख करोड़ से विकास को रफ्तार

केंद्रीय करों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर व योजनाओं को मिलेगा बूस्ट

रेल, उद्योग, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खास फोकस

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार के खजाने से करीब 4.26 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह राशि पिछले बजट की तुलना में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तेज़ी मिलेगी। केंद्रीय करों से राज्यों को मिलने वाले हिस्से में यूपी को सबसे बड़ा भाग मिलेगा। वित्त विभाग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यांश, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, कैपिटल असिस्टेंस और सेंट्रल सेक्टर मद में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत रखी गई है, जो देश में सबसे अधिक है। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से राज्य को बड़ी धनराशि प्राप्त होगी। इसके अलावा 200 परंपरागत औद्योगिक क्लस्टर के पुनर्जीवन, एमएसएमई और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा देने जैसी घोषणाओं से भी यूपी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

रेल कॉरिडोर, उद्योग और ग्रामीण योजनाओं से मिलेगा फायदा

बजट में घोषित सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से दो दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी-उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। इससे वाराणसी समेत करीब दस जिलों को सीधा लाभ होगा। राज्य में पहले से वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का यह पहला बड़ा विस्तार होगा। ग्रामीण और पारंपरिक उद्योगों के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज और हैंडलूम योजनाएं शुरू की जाएंगी। खादी, हथकरघा, ओडीओपी, चमड़ा, खेल और हस्तशिल्प उद्योग को मजबूती मिलेगी। जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, हर जिले में ट्रॉमा सेंटर खोलने और पर्यटन स्थलों पर गाइड प्रशिक्षण जैसी घोषणाएं भी यूपी के लिए अहम मानी जा रही हैं।

यूपी को मिलने वाली राशि और योजनाओं का लाभ

2.68 लाख करोड़ – केंद्रीय करों में राज्यांश	**1.10** लाख करोड़ – केंद्र प्रायोजित योजनाएं
18,000 करोड़ – सेंट्रल सेक्टर	**20,000** करोड़ – कैपिटल असिस्टेंस
10,000 करोड़ – केंद्रीय ऋण व अन्य मद	

हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

काशी से दिल्ली (871 किमी)

अनुमानित रूट

दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, नया इटावा, दक्षिण कन्नौज/कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, नई भदोही, वाराणसी

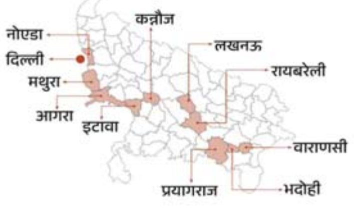

काशी से सिलीगुड़ी (702 किमी)

अनुमानित रूट

वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, नवादा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, हावड़ा, सिलीगुड़ी

नोट- सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर रूट की जानकारी नहीं दी गई है।

फायदा

- हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनें 300-350 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी। सामान्य रेलवे ट्रैक पर 120 से 150 तक की स्पीड होती है।
- तेज स्पीड से ट्रेन चलने से वक्त बचेगा। काशी से दिल्ली की यात्रा 4 से 5 घंटे में हो सकेगी। अभी 11 से 12 घंटे लगते हैं।
- आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- सड़क और हवाई यातायात पर दबाव कम होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा।
- हाई स्पीड रेल स्टेशनों के आसपास नई टाउनशिप और बुनियादी ढांचे विकसित होंगे।

मुख्य योजनाओं का लाभ

- हैंडलूम व ग्राम स्वराज योजना से पूर्वांचल व ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा
- वाराणसी में जलपोत मरम्मत केंद्र की स्थापना
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले 25 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार
- वाराणसी, मथुरा, आगरा, लखनऊ समेत पर्यटन क्षेत्रों में गाइड प्रशिक्षण
- ग्रामीण महिलाओं के लिए शी-मार्ट नेटवर्क
- हर जिले में ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल क्षमता विस्तार
- सारनाथ और हस्तिनापुर का सांस्कृतिक विकास
- इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल निर्माण में यूपी को बढ़त
- एमएसएमई सेक्टर को 10 हजार करोड़ का समर्थन
- कैंसर, डायबिटीज समेत दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती
- सेमीकंडक्टर निवेश प्रोत्साहन से औद्योगिक लाभ

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com